



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 2014/2026

प्रियांशु

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	: अरविंद कुमार साहू
विपक्षी के अधिवक्ता	: जी.ए., नेहा रानी, पवन कुमार यादव, सत्यवेंद्र सिंह यादव

कोर्ट नं. - 65

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी

1. सूची दोहरायी गई है। कोई भी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद या बाल कल्याण समिति, बदायूं के लिए उपस्थित नहीं होता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पीड़िता बड़ी है और पीड़िता अपनी मर्जी और सहमति से आवेदक के साथ गई थी। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में विशेष रूप से कहा है कि वह अपनी मर्जी से मथुरा में आवेदक के साथ गई थी और गोवर्धन मंदिर में शादी की थी। इसी तरह का बयान पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में भी कहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक और पीड़िता ने अपनी मर्जी और सहमति से विवाह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किया है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक को गुप्त उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य प्रस्तुतियाँ भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर लागू करना उचित समझे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आवेदक 16.12.2025 से जेल में बंद है।

4. दूसरी ओर, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि आवेदक और पीड़ित के बीच विवाह संपन्न हो गया है और आवेदक को जमानत पर रिहा करने की स्थिति में उसे कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि विवाह को पंजीकृत करने के लिए आवेदक पर एक शर्त लगाई जा सकती है।

5. उपरोक्त प्रस्तुतियों के जवाब में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पीड़िता अपने माता-पिता के घर में रह रही है और यदि पीड़िता को उसके ससुराल भेज दिया जाता है, तो विवाह पंजीकृत किया जाएगा।

6. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जैसे ही आवेदक जेल से रिहा होगा, पीड़ित को वैवाहिक घर भेज दिया जाएगा।

7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही को पूर्व-परीक्षण चरण में नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए, वह किसी भी भोग के योग्य नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, साक्ष्य की प्रकृति, और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। इसलिए जमानत आवेदन की अनुमति है।

9. आवेदक **प्रियांशु**, जो केस क्राइम नंबर 0035/2025, सेशंस केस नंबर 1837/2025 में धारा 137(2), 87, 64 बी.एन.एस. और पॉस्को एक्ट की धारा 3/4 के तहत पुलिस स्टेशन मुजरिया, जिला बदायूं आरोपी है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उसी राशि के दो स्थानीय जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i) आवेदक अपनी रिहाई की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण कराएगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी या परेशान नहीं करेगा।
- iv) आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- v) आवेदक उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके लिए आवेदक पर आरोप लगाया गया है, या आयोग पर संदेह है।
- vi) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी)

फरवरी 20, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”